

## विमुद्रीकरण की प्रक्रिया: एक विश्लेषण

प्रोफेसर (डॉ.) रेनु जटाना\*  
कन्हैया लाल\*\*

### 1. परिचय

मोदी सरकार द्वारा 8 नवम्बर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा की गई, जिससे देश में प्रचलित ₹. 500 व ₹. 1000 के वैधानिक नोट रात्रि 12 बजे से अमान्य हो गए। उस समय से ही नोटबंदी के औचित्य पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। अब जबकि नोटबंदी को एक साल पूर्ण हो गया है। तब यह विश्लेषण आवश्यक हो गया है कि मोदी सरकार द्वारा उठाया गया कदम क्या साबित हुआ "एक जल्दबाजी में किया गया फैसला अथवा बेहतर भविष्य हेतु उठाया कठोर कदम।" अतः इस पत्र में सर्वप्रथम नोटबंदी (विमुद्रीकरण) का अर्थ, उद्देश्य व इतिहास बताया गया है। फिर एक वर्ष के उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर विमुद्रीकरण की आर्थिक आलोचनात्मक समीक्षा की गई है, जिसके अन्तर्गत इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं से संबंधित विभिन्न आयामों को छूने का प्रयत्न किया गया है। एवं उसी आधार पर अंत में समीक्षा की गई है।

### 2. वैधानिक मुद्रा, विमुद्रीकरण

#### विमुद्रीकरण: परिभाषा व महत्व ;

विमुद्रीकरण, वह प्रक्रिया है जिसके तहत देश का केन्द्रीय बैंक काले धन अथवा नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए चलन में पुरानी मुद्रा की वैधानिकता समाप्त करके नयी मुद्रा जारी कर देता है। इस प्रकार जिसके पास काला धन होता है वह उसे नई मुद्रा में बदलने का साहस नहीं कर पाता है तथा इस प्रकार अवैध तरीके से अर्जित कालाधन व नकली करेंसी स्वतः ही नष्ट हो जाती है।

#### उद्देश्य ;

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना
- कालेधन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना
- आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना
- नकली नोट का चलन बंद करना

#### प्रभाव ;

- गरीब, नियामिडिल क्लास एवं मध्यम वर्ग के लिये नये अवसर पैदा करना।
- रियल स्टेट की कीमतें, स्वास्थ्य सुविधायें एवं उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुँच में लाना।
- हथियारों की तस्करी व आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करवाना।

\* विभागाध्यक्ष, बैंकिंग व व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड मेनेजमेन्ट स्टडीज (यू सी सी एम एस), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

\*\* व्याख्याता, वाणिज्य संकाय, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरौही, राजस्थान।

foephdj.k dk bfrgkl

भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास काफी पुराना है। अब तक भारत में तीन बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है जो निम्नानुसार है –

- प्रथम – भारत में पहली बार विमुद्रीकरण सन् 1946 ई. में किया गया था। तब 1000 रु. व 10,000 रुपये के नोटों को बन्द किया गया था। लेकिन उस समय इन नोटों की पहुँच केवल अमीर वर्ग तक ही सीमित थी अतः यह नोटबंदी, अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं कर पाई।
- द्वितीय – दूसरी बार विमुद्रीकरण जनता सरकार ने सन् 1978 ई. में किया। तब 1000 रुपये, 5000 रुपये व 10,000 रुपये के नोट बंद किये गये थे। जिसका तात्कालिक उद्देश्य काला धन रोकना था।
- तृतीय – तीसरी बार मोदी सरकार द्वारा 8 नवम्बर 2016 को किया गया। जिसमें 500 रुपये व 1000 रुपये के नोट बंद किये गये थे। इन नोटों के रूप में मौजूदा 86 प्रतिशत मुद्रा बंद कर दी गई। जिसका मूल्य 15.44 लाख करोड़ रुपये था। इन नोटों का विमुद्रीकरण करने पर RBI ने 10 नवम्बर 2016 को लाल किले के चित्र वाले 500 रुपये के नोट तथा मंगलयान के चित्र वाले 2000 रुपये के नोट जारी किये गये।

foephdj.k dk l dkjkRed iHkko @igyq

देश में नोटबंदी का सकारात्मक असर निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा गया –

- dky/ku ij vdrk
  - वह धन जो गैर-कानूनी तरीके से अर्जित किया गया हो, अर्थात् जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो, वह काले धन की श्रेणी में आता है। कालाधन एक व्यापक अवधारणा है जिसका रूप रियल स्टेट, नकद या स्वर्ण के रूप में हो सकता है। नोटबंदी ने काले धन पर जबरदस्त प्रहार किया है जो निम्न प्रकार है –
    - fj; y LVW % रियल स्टेट, कालाधन रखने का हमेशा से पसंदीदा क्षेत्रों में से महत्वपूर्ण रहा है। रियल स्टेट में कालाधन निवेश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नोटबंदी का इस क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ा है। आँकड़े बताते हैं कि हाउसिंग लोन की वृद्धि दर में करीब 7% कमी आई है। मेट्रो शहरों में मकानों की बिक्री में 40% के आसपास कमी हुई है। नये प्रोजेक्ट 61% कम लॉन्च हुए हैं। नये मकानों की कीमत में 10% की कमी तथा पुराने मकानों की कीमत 25% तक कम हुई है। ये तथ्य बताते हैं कि नोटबंदी की वजह से कालाधन वालों पर गहरी चोट हुई है।
    - Lo.kl % काले धन का एक स्वरूप स्वर्ण भी होता है। नोटबंदी का इस क्षेत्र पर भी सकारात्मक असर देखा गया है। सरकार के कड़े नियम तथा नोटबंदी से सोने की बिक्री में 35% तक की कमी हुई है। बुलियन ट्रेडर्स के अनुसार, नोटबंदी के कारण गोल्ड व्यापार में बी 2 बी (बिजनेस टू बिजनेस) कारोबार में कालेधन की एन्ट्री बंद हो गई है। लेकिन बी टू सी (बिजनेस टू कन्ज्यूमर) में अभी भी कालाधन चल रहा है।
    - udn % नोटबंदी का नकद के रूप में काले धन पर प्रत्यक्ष प्रहार हुआ है। आँकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि नोटबंदी के 53 दिन में आयकर विभाग ने 3185 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया जिसमें 428 करोड़ नकद मिले हैं। देश में नोटबंदी के बाद 23.22 लाख खातों में लगभग 3.68 लाख करोड़ रुपये का संदिग्ध नकद जमा हुआ है। 16,000 करोड़ रुपये की नकदी वापस नहीं आई है। साथ ही 21% करेंसी सर्कुलेशन में कमी देखी गई। चौंकाने वाला सच यह है कि देश की जनसंख्या के 0.00011% लोगों ने देश में उपलब्ध कुल नकद जमा का 33% जमा किया है। यह सब आँकड़े दर्शाते हैं कि कालाधन रखने वाले लोगों को एक परिधि में बाँध लिया है। अब उनकी पहचान करना आसान है।

• **Othl dEi uh dh i gpk**

नोटबंदी से एक फायदा यह भी हुआ है कि इसकी सहायता से मुखौटा कम्पनी / फर्जी कम्पनी की पहचान करना आसान हुआ है। सेबी ने नोटबन्दी के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ विशेष कदम उठाये, जिससे फर्जी कम्पनी की पहचान करके, उन पर कठोर कारवाई करना शामिल है। निष्क्रिय कम्पनियाँ, गलत लोगों के हाथ का खिलौना बन जाती है। तथा इस प्रकार शेयर बाजार, कालेधन की शरणस्थली बन जाती है। नोटबन्दी के बाद 2.97 लाख मुखौटा कम्पनी की पहचान हुई, इन कम्पनियों को नोटिस जारी करने के बाद कानूनी कारवाई के जरिये 2.24 लाख कम्पनियों का पंजीकरण रद्द किया गया। जिन कम्पनियों में दो साल से कोई भी काम नहीं हुआ है उन कम्पनियों के बैंक खातों के लेन-देन को रोकने की कारवाई की गई तथा बैंक खातों को फ्रिज भी किया गया। साथ ही इनके 3 लाख निदेशक की पहचान करके उन्हें अयोग्य घोषित किया गया तथा उनके किसी भी अन्य कम्पनी के निदेशक बनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार नोटबंदी से धीरे-धीरे कालाधन का कचरा साफ हो रहा है।

• **udnfgohu vFkD; oLFkk dh vkj c<rs dne**

नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था में कैशलैस का सुनहरा भविष्य लेकर आया है। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि डिजिटल (Digital) लेनदेन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। ऑकड़ों से पता चलता है कि नोटबंदी के शुरुआती हफ्तों में डिजिटल पेमेंट में 300 फीसदी का इजाफा हुआ है। नोटबंदी के दिन तक रोजाना 17 लाख लेनदेन ई-वॉलेट से हो रहे थे, एक महीने में इसकी संख्या बढ़कर 63 लाख हो गई। एक साल में ऑनलाइन पेमेंट 57% बढ़ने का अनुमान है। तथा डिजिटल पेमेन्ट अब भी (अगस्त-सितम्बर 2017 के बीच में) 13.5% की दर से बढ़ रहा है। इसी प्रकार यदि बात डेबिट और क्रेडिट कार्ड की करें तो वर्ष 2015-2016 में डेबिट कार्ड से 1.6 लाख करोड़ रुपये व क्रेडिट कार्ड से 2.4 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन हुए हैं जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर क्रमशः 3.3 लाख करोड़ रुपये और 3.3 लाख करोड़ रुपये के हो गये। स्पष्ट है कि डेबिट कार्ड में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। यह वृद्धि दुगुनी से भी अधिक रही है। अगस्त 2016 से अगस्त 2017 के मध्य डिजिटल लेन-देन में 58% की वृद्धि देखी गयी। स्वाइप मशीन तथा पी ओ एस (POS) मशीनों में भी काफी वृद्धि हुई है। नोटबंदी से पहले युपीआई (UPI) को ज्यादा पसंद नहीं किया गया लेकिन नोटबंदी के बाद इनमें भी काफी सकारात्मक वृद्धि हो गई है। नोटबंदी ऑनलाइन व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए भी बहुत बड़ा अवसर बनकर आयी है। एक सर्वे के मुताबिक नोटबंद के बाद 78% लोगों ने ऑनलाईन शॉपिंग शुरू की है। स्पष्ट है कि भारत कैशलैस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

• **udn dk pyu de gpk**

नकद भ्रष्टाचार का वह रूप है जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है। नोटबंदी की वजह से नकद की जगह डिजिटल लेनदेन बढ़े हैं। जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। नोटबंदी का उद्देश्य देश में नकदी के मालिक की पहचान करना भी था तथा नोटबंदी इस उद्देश्य में सफल भी रही है। ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि अब तक 15.28 लाख करोड़ रुपये अधिकृत रूप से बैंकिंग क्षेत्र में आ गये हैं। अतः अब नकदी का सिरा भी मिल गया है। इसमें से 1.6 से 1.7 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन संदिग्ध है। तथा इस दिशा में जाँच कार्य जारी है। अतः उम्मीद के अनुसार नोटबंदी से नकदी में कमी अंततः कालाधन और भ्रष्टाचार में कमी ला रही है।

• **vkrdh QfMx ij jkd yxh**

नोटबंदी से आतंकी घटना में कमी देखी गई है। नोटबंदी से जाली नोट रद्दी में बदल गये जिसका असर आतंकी घटनाओं पर भी पड़ा है। कश्मीर में आतंकवादी द्वारा नये नोटों को लूटने हेतु बैंकों में डाका डालना, उनकी हताशा को बताता है। नोटबंदी के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 75 प्रतिशत तक की कमी आई है। तथा वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी 20 प्रतिशत की कमी हुई है। नोटबंदी अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में भी पूरी तरह सफल होती दिखाई दे रही है।

- **अर्थव्यवस्था के संगठित होने से निर्धन वर्ग के लोगों को फायदे मिलने लगे हैं।**

अर्थव्यवस्था के संगठित होने से निर्धन वर्ग के लोगों को फायदे मिलने लगे हैं। तथा वे उन सुविधाओं को प्राप्त करने लगे हैं जिनसे अब तक वंचित थे। अब कर्मचारियों को पूरा वेतन सीधे उनके खाते में जमा हो रहा है। 1.30 करोड़ कर्मचारी ESIC में पंजीकृत हुए हैं। जिससे इनको सभी सामाजिक सुरक्षाएँ व स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। सरकार द्वारा मजदूरी अधिनियम में आवश्यक संशोधन उनके लिए सोने पर सुहागा साबित हो रहा है।

- **नोटबंदी का असर, राजस्व प्राप्ति पर सकारात्मक हुआ है।**

नोटबंदी का असर, राजस्व प्राप्ति पर सकारात्मक हुआ है। करदाता की संख्याओं में वृद्धि व कर आधार में विस्तार से राजस्व में व्यापक वृद्धि हुई है। आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में करदाताओं की संख्या 66.53 लाख थी जो 2016-17 में बढ़कर 84.21 लाख हो गई यानि 26.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार ई-रिटर्न में 27.95 प्रतिशत वृद्धि के साथ बढ़कर वर्ष 2017-18 में 3.01 करोड़ हो गये। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी गतवर्ष की तुलना में 34.25 प्रतिशत बढ़ गया है। कुल मिलाकर देश में कराधार में विस्तार अघोषित आमदनी को वित्तीय तंत्र में लाना, अग्रिम कर भुगतान इत्यादि पैमाने पर भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। इन सबका राजस्व प्राप्ति पर भी सकारात्मक असर पड़ा है।

- **नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव यह लायी है कि भारत की घरेलू बचत अब वित्तीय बाजार की ओर मुड़ती नजर आ रही है।**

नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव यह लायी है कि भारत की घरेलू बचत अब वित्तीय बाजार की ओर मुड़ती नजर आ रही है। आँकड़ों के आइने से देखा जाये तो, RBI के अनुसार भारतीयों की घरेलू बचत (घरों से) वर्ष 2015-16 में GDP का 1.4% था जो 2016-17 में घटकर (-) 2.1% हो गयी। अर्थात् बैंक जमा व शेयर में निवेश बढ़ता जा रहा है। म्युचुअल फण्ड में वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में 155% वृद्धि देखी गई है। यह तेजी दर्शाती है कि लोग बचत के लिए परम्परागत माध्यमों की बजाय इन वित्तीय उत्पादों की तरफ रुख कर रहे हैं।

- **नोटबंदी से बैंकों की जमा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर ब्याज दरों पर पड़ा है।**

नोटबंदी से बैंकों की जमा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर ब्याज दरों पर पड़ा है। अत्यधिक जमाओं को देखते हुए बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में 1 फीसदी तक की कमी (कटौती) कर दी है। नतीजन बैंकों के होम लोन व कार लोन भी सस्ते हो गये हैं जिसका फायदा अंततः आम आदमी को हुआ है।

- **नोटबंदी, मुद्रास्फीति के लिहाज से भी सफल रही है।**

नोटबंदी, मुद्रास्फीति के लिहाज से भी सफल रही है। नोटबंदी से मुद्रास्फीति में लगातार 8 माह गिरावट देखी गई है। मुद्रास्फीति जो अक्टूबर 2016 में 4.2% थी वह जून 2017 में घटकर 1.54% पर आ गयी। (CPI) अतः आम आदमी को मंहगाई से राहत मिली है।

- **विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है।**

विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। नोटबंदी के समय जिन नकारात्मक आशंकाओं को व्यक्त किया जा रहा था वे आशंकाएं अब सच होती नजर आ रही हैं जो निम्न प्रकार हैं –

- **नोटबंदी के समय अधिकांश अर्थशास्त्रियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह भी शामिल हैं, ने**

आशंका व्यक्त की थी कि नोटबंदी तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगी अर्थात् विकास दर में गिरावट होगी। अब यह आशंका पूरी तरह से सच साबित होती नजर आ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 की पहली

तिमाही में विकास दर 7.9% थी जो वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में घटकर 5.7% पर आ गई। यह पिछले तीन वर्ष में सबसे निचले स्तर पर है। नतीजन हमने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा खो दिया है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। जो निम्न प्रकार है -

- **df"k %** कृषि का भारतीय GDP में 17.9% योगदान है तथा यह क्षेत्र भारत की जीवन रेखा भी है। नोटबंदी का इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। नोटबंदी के दौरान इस क्षेत्र की विकास दर 6.9% थी जो घटकर जून 2017 में 2.34% पर आ गई। साथ ही गत वर्ष की तुलना में अप्रैल-जून 2017 में कृषि उपजों की कीमतें 2% तक गिरी है।
- **es; QDpj %** इस क्षेत्र की GDP में 17% की भागीदारी तथा 3 करोड़ रोजगारदाता है। नोटबंदी का इस क्षेत्र पर जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र की विकास दर अक्टूबर-दिसम्बर 2016 में 8.3% थी वह जनवरी-मार्च 2017 में घटकर मात्र 1.6% रह गयी।
- **l fol l DVj %** नोटबंदी का असर सेवा क्षेत्र पर भी नकारात्मक रहा है। पिछले तीन सालों में पहली बार इस क्षेत्र की विकास दर कम हुई है। जून 2015 के बाद पहली बार ऑर्डर में कमी देखी गई है। तथा सर्विस सैक्टर का PMI नवम्बर 2016 में 46.7 रहा (ये 50 से कम यानि सैक्टर घट रहा है)। नोटबंदी की विफलता का आलम यह कि आर.बी.आई. को वर्ष 2017-18 की विकास दर 7.3% से घटाकर 6.7% करनी पड़ी।

• **jkst xkj ea deh**

नोटबंदी का असर रोजगार पर भी पड़ा है। नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था एक दम लड़खड़ा गई है। जिसका खामियाजा लोगों को अपनी नौकरी गंवाकर उठाना पड़ा। नोटबंदी से निर्माण क्षेत्र में लगभग 30-40% रोजगार में कमी आई है। सबसे ज्यादा नुकसान असंगठित क्षेत्र में हुआ है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां गंवानी पड़ी है। लेबर ब्यूरो के अनुसार, अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 के मध्य 1.52 लाख अस्थायी तथा 46 हजार पार्ट टाइम नौकरी गई है। नोटबंदी की घोषणा के चार माह बाद कुल मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 15 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इस प्रकार नोटबंदी ने रोजगार क्षेत्र में काफी बुरा प्रभाव डाला है।

• **dkys /ku dks jkcdus ea ukdke**

नोटबंदी करते समय सरकार ने जोर देकर कहा था कि नोटबंद से नकदी का 2.5 लाख करोड़ रुपये बैंकिंग तंत्र में वापस नहीं लौटेगा। लेकिन सरकार का यह दावा सरासर गलत साबित हुआ, RBI के अनुसार नोटबंदी के बाद 99% नकदी बैंकिंग तंत्र में वापस आ गई है। अतः सरकार का काला धन रोकने की दावे बाजी असफल रही। साथ ही नोटबंदी की योजना की घोषणा के 4 दिन के अंदर ही 25 टन अधिक स्वर्ण बिक गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोगों को अपना कालाधन बदलने का पर्याप्त समय व तरीका मिल गया था। इस प्रकार नोटबंदी कालेधन के सन्दर्भ में निष्फल रही।

• **udyh ukd/ka i j udsy ugha**

नोटबंदी का एक उद्देश्य नकली नोटों की रोकथाम भी था। लेकिन नोटबंदी अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में भी असफल रही है। सरकार के अनुसार नोटबंदी के बाद मात्र 19.53 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। इससे भी बड़ी विडम्बना यह रही कि सरकार दावा कर रही थी कि नये नोट आने के बाद नकली नोटों की समस्या समाप्त हो जाएगी। जबकि नये नोटों के नकली नोट भी चलन में आ गए। अर्थात् नकली नोट बनाने वाले नये नोटों की नकल बनाने में भी सफल रहे हैं।

- **दशक के अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी तीव्र बताई थी।**

सरकार ने नोटबंदी के बाद कैंशलेस अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी तीव्र बताई थी। जबकि हकीकत इससे परे है। RBI के अनुसार सभी तरह के डिजिटल ट्रांजेक्शन के लेन-देन 5% से भी कम है। भारत में मात्र 3 करोड़ लोग ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिंगापुर, नीदरलैंड, जैसे देशों में कैंशलेस ट्रांजेक्शन 60% से भी अधिक है। जबकि भारत में यह दर मात्र 2% है। कैंशलेस के सन्दर्भ में सरकार की कथनी और करनी में भी काफी फर्क रहा है सरकार एक तरफ तो डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ डिजिटल ट्रांजेक्शन पर चार्ज भी वसूल करती है जो कि समझ से परे है।

- **जन धन खातों को खुलवाने का मूल उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों में वित्तिय समावेशन बढ़ाना था।**

लेकिन नोटबंदी के दौरान यही जन-धन खाते काले धन को सफेद धन में बदलने का औजार साबित हुए। ऑकड़ों के अनुसार नोटबंदी के बाद 100 दिनों में 2.26 करोड़ नये जन-धन खाते खुले तथा तीन महीनों में जन-धन खातों में 19084 करोड़ रुपये जमा हुए। शून्य रुपये वाले जनधन खातों का प्रतिशत सितम्बर 2016 में 24.1% था जो घटकर अगस्त 2017 में 21.4% हो गया। इस प्रकार लोगों ने कालेधन को बदलने हेतु जन-धन खातों का उपयोग किया है।

- **अधिकांश आलोचकों का मानना है कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है।**

सरकार द्वारा 50 दिन में 65 नियम बदलना सरकार की अपर्याप्त तैयारी को दर्शाती है। बैंक व एटीएम के आगे लम्बी लाइनें इसकी अव्यवस्था के सबूत रही। आलोचक मानते हैं कि सरकार को बड़ा आर्थिक कदम उठाने से पहले कुछ उचित कदम उठाये जाने चाहिए थे, खासकर लघु व मध्यम उद्योगों के लिए जो कि बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करते हैं।

- **कृषि एवं परिवहन नकद का व्यापार है। अतः नोटबंदी का किसानों पर गहरा आघात हुआ है।**

नोटबंदी का समय खरीफ की फसल बेचने तथा रबी की फसल की बुवाई का समय था अतः किसानों पर दोहरा आघात हुआ है। एक तरफ तो नोटबंदी की वजह से उनकी खरीफ की कीमत 40% तक गिरी साथ ही बिक्री भी मात्र 25-50 प्रतिशत ही हो सकी। वहीं दूसरी तरफ नकद के अभाव में खाद, बीज खरीद नहीं पाये जिससे रबी की बुवाई भी प्रभावित हुई है। नतीजन किसानों के कर्ज और बढ़ गये हैं।

- **नोटबंदी से व्यापार जगत पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।**

नोटबंदी के बाद 1 साल के दौरान व्यापार में 40% तक की कमी पाई गई है। जिससे उबरने में काफी समय लगेगा।

- **उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि नोटबंदी के संबंध में दोनों पहलु (पक्ष-विपक्ष) मौजूद हैं, नोटबंदी के सकारात्मक पहलू को देखा जाए तो नोटबंदी से निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में सुधार आया है।**

नोटबंदी के बाद काले-धन पर अंकुश, रियल स्टेट की कीमतों पर लगाम, जाली नोटों का अर्थव्यवस्था से गायब होना, नकसली व आतंकी घटनाओं में कमी होना, यह सब घटनाएँ इसके सकारात्मक प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। साथ ही नोटबंदी के बाद देश एक साफ-सुथरी, ईमानदार व पारदर्शी वित्तिय तंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। जिससे दूरगामी परिणाम भी अच्छे आयेंगे। नोटबंदी के प्रमुख समर्थक रिचर्ड एच. थेलर (अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता), नंदर नीलकेणी (UID के पहले अध्यक्ष), चंदा कोचर (CEO, ICICI Bank) इत्यादि हैं।

दूसरी तरफ, जब नोटबंदी के नकारात्मक पहलुओं पर नजर डालने से ज्ञात होता है कि नोटबंदी अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में असफल रही है। घटती विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी, आमजन की बढ़ती परेशानी इस बात के स्पष्ट संकेत है कि नोटबंदी फायदे की जगह घाटे का सौदा साबित हो रही है। नोटबंदी के विरोध में प्रमुख व्यक्ति, प्रो. अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता), रघुराम राजन (पूर्व RBI गवर्नर), ज्यां ट्रेज (अर्थशास्त्री) इत्यादि। डा. मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को “संगठित लुट” तथा “कानूनी डाका” की संज्ञा दी है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नोटबंदी कुछ कारणों की वजह से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से ही सफल रही है। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त हो रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि नोटबंदी के अल्पकालीन परिणाम आशातीत नहीं रहे हैं लेकिन भविष्य के प्रति उम्मीद अब भी बरकरार है।

। nHkZ xfk । ph

- ❖ व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर
- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था, अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण, 2017
- ❖ राजस्थान पत्रिका दिनांक 09-11-2016
- ❖ दैनिक भास्कर दिनांक 09-11-2016
- ❖ दैनिक नवज्योति दिनांक 09-11-2016
- ❖ राजस्थान पत्रिका दिनांक 08-11-2017
- ❖ दैनिक भास्कर दिनांक 08-11-2017
- ❖ दैनिक नवज्योति दिनांक 08-11-2017
- ❖ जागरूक टाइम्स दिनांक 08-11-2017
- ❖ <http://www.freepressjournal.in/featured-blog/indias-history-with-demonietisation- from 1946-2016>.
- ❖ <http://mumbai.mirror.indiatimes.com/news/india/histry-of-demonietisations-in- world>.

